भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं.1516
12 दिसंबर, 2025 को उत्तर देने के लिए

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में रोजगार सृजन

1516. श्रीमती राजाथी:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की रोजगार सृजन तथा देश के समग्र औद्योगिक विकास में योगदान देने की क्षमता का आकलन किया है;
(ख) यदि हॉं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान पंजीकृत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं, अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) एवं अल्पसंख्यक समुदाय के श्रमिकों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
(घ) सरकार द्वारा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क) और (ख): वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण 2022-23 की रिपोर्ट के अनुसार, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र , संगठित विनिर्माण क्षेत्र में सबसे ज़्यादा रोज़गार देने वालों में से एक है, जो कुल पंजीकृत/संगठित क्षेत्र में 12.91% रोज़गार देता है। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का 2024-25 में कुल कृषि खाद्य पदार्थ के निर्यात में 20.4% हिस्सा है और 2023-24 (प्रथम संशोधित अनुमान के अनुसार) के दौरान देश में विनिर्माण सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) में इसका हिस्सा 7.93% है। इस क्षेत्र में सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) 2014-15 में रु. 1.34 लाख करोड़ से बढ़कर 2023-24(प्रथम संशोधित अनुमान के अनुसार) में रु. 2.24 लाख करोड़ हो गया है।

(ग) और (घ): सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने नियमित सर्वेक्षण यानी वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण किया है, जिसमें पंजीकृत क्षेत्र में विनिर्माण इकाइयां (खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र सहित) शामिल हैं। वर्ष 2023-24 के वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण (एएसआई) की नवीनतम रिपोर्ट केअनुसार , खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में महिलाओं के राज्य-वार रोज़गार का विवरण **अनुबंध** में दिया गया है। एएसआई में अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अल्पसंख्यक समुदाय के कार्मिकों से जुड़ी जानकारी कैप्चर नहीं की गई है ।

इसके अलावा, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) अपनी दो केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं अर्थात् प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) के माध्यम से संबंधित अवसंरचना की स्थापना/विस्तार को प्रोत्साहित कर रहा है । इसके अलावा, एमओएफपीआई द्वारा केंद्र प्रायोजित प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना भी लागू की जा रही है । ये तीनों योजनाएं मांग आधारित हैं और पूरे देश में लागू की जा रही हैं और ये खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में कृषि-इतर रोजगार के अवसर सृजित कर रही हैं। दिनांक 31अक्तूबर, 2025 तक, देश भर में पीएमकेएसवाई की घटक योजनाओं के अंतर्गत चल रही परियोजनाओं से 4.53 लाख प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। दिनांक 31अक्तूबर 2025 तक, देश भर में पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत 4.88 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। दिनांक 31 अक्टूबर , 2025 तक, देश भर में पीएलआईएसएफपीआई के तहत 3.39 लाख प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं।

*****

अनुबंध

"खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में रोजगार सृजन" के संबंध में दिनांक 12 दिसंबर , 2025 को उत्तर हेतु राज्य सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 1516 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में महिलाओं को रोज़गार (प्रत्यक्ष नियोजित) का राज्य-वार अनुमान

		महिलाएं (प्रत्यक्ष नियोजित)		
क्र.सं.	**राज्य**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	24	33	36
2	आंध्र प्रदेश	47102	44492	50454
3	अरुणाचल प्रदेश	248	237	282
4	असम	7276	8468	8223
5	बिहार	707	626	1000
6	चंडीगढ़	51	36	34
7	छत्तीसगढ	1052	1848	2093
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	160	196	220
9	दिल्ली	444	183	259
10	गोवा	833	1564	945
11	गुजरात	9562	10704	11112
12	हरियाणा	1212	863	1198
13	हिमाचल प्रदेश	429	471	633
14	जम्मू और कश्मीर	302	287	352
15	झारखंड	872	557	608
16	कर्नाटक	15784	20488	21213
17	केरल	43131	38999	38727
18	लद्दाख	0	15	9
19	मध्य प्रदेश	1750	2639	5637
20	महाराष्ट्र	8738	8083	8108
21	मणिपुर	252	150	288
22	मेघालय	67	65	82
23	मिजोरम	28	28	30
24	नागालैंड	22	25	23
25	ओडिशा	3691	2641	3592
26	पुदुचेरी	284	497	432
27	पंजाब	1322	9693	2667
28	राजस्थान	1404	2311	1654
29	सिक्किम	445	470	491
30	तमिलनाडु	48869	45544	48941
31	तेलंगाना	5302	6569	4980
32	त्रिपुरा	295	222	237
33	उत्तर प्रदेश	3016	3404	4373
34	उत्तराखंड	708	797	850
35	पश्चिम बंगाल	4802	3845	4633

स्रोत: वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण, 2021-22, 2022-23 और 2023-2024

*****